

प्रेस विज्ञप्ति
तत्काल विज्ञप्ति के लिए

मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में 'सभी मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर
पोर्ट के विकास' को मंजूरी दी

मुंबई, 20 जून, 2024 – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानु के निकट

वधावन में वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (वीपीपीएल) द्वारा एक प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने को अपनी मंजूरी दे

दी है। यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जनेपप्रा) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) द्वारा गठित एक एसपीवी है, जिसकी हिस्सेदारी क्रमशः 74% और 26% है। वधावन पोर्ट को 'लैंड लॉर्ड' मॉडल पर महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में सभी मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ ने

कहा, "जैसा कि हम वधावन बंदरगाह के विकास की ओर अग्रसर हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जनेपप्रा) और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड के बीच सहयोगात्मक प्रयास का अनावरण करते हुए हमें बहुत गर्व और उत्सुकता हो रही है। इस गठबंधन का उद्देश्य बढ़ते समुद्री यातायात को पूरा करना है, जो विकास और अवसरों से भरे एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित करता है। इस परियोजना को जेएनपीए और एमएमबी के एसपीवी वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। हम माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और माननीय सचिव, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय श्री टी के रामचंद्रन के नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए बहुत आभारी हैं।

वधावन बंदरगाह परिव्यय भूमि अधिग्रहण के घटक सहित कुल परियोजना लागत ₹ 76,220 करोड़ है। इसमें मुख्य

बुनियादी ढांचा, टर्मिनल और पीपीपी मोड में अन्य वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा शामिल होगा। बंदरगाह के बुनियादी

ढांचे में 9 कंटेनर टर्मिनल, प्रत्येक 1000 मीटर लंबाई, 4 बहुउद्देशीय बर्थ, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो-रो बर्थ, एक

तटीय कार्गो बर्थ और एक तटरक्षक बर्थ शामिल हैं। इस परियोजना में अपतटीय क्षेत्र में 1,448 हेक्टेयर भूमि का पुनर्ग्रहण और 10.14 किलोमीटर लंबे ब्रेकवाटर, कंटेनर/कार्गो भंडारण क्षेत्रों का निर्माण शामिल है। कैबिनेट ने MoRTH द्वारा बंदरगाह और राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क संपर्क स्थापित करने और MoR द्वारा मौजूदा रेल नेटवर्क और आगामी समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडोर को रेल संपर्क प्रदान करने को भी मंजूरी दी। भारत की व्यापार नीतियों और समुद्री परिवहन क्षेत्र के विकास के परिणामस्वरूप देश में कंटेनरीकरण में उच्च वृद्धि हुई है। वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किए गए एक व्यापक रोडमैप के साथ भारत का समुद्री क्षेत्र बदलने के

लिए तैयार है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार अमृत काल विजन 2047, समुद्री भारत विजन 2030 पर आधारित है और इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय बंदरगाहों का विकास करना और अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय शिपिंग और एक स्थायी समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना है। पश्चिमी तट पर तीन प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग

बंदरगाहों की क्षमता का 2029 तक पूरा उपयोग किया जाएगा और 24 मिलियन TEU की सीमा तक क्षमता की आवश्यकता है और यह क्षमता वधावन बंदरगाह से पूरी होने की उम्मीद है। वधावन में प्रस्तावित डीप ड्राफ्ट ऑल-वेदर मेजर पोर्ट राष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग क्षमता को 23.2 मिलियन टीईयू तक बढ़ाएगा और 24,000 टीईयू ले जाने में

सक्षम मेगा आकार के कंटेनर जहाजों को बुलाने की सुविधा प्रदान करेगा। वधावन बंदरगाह के विकास के साथ, भारत दुनिया के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाहों में से एक होगा। बनाई गई क्षमताएं IMEC (भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा) और INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा) के माध्यम से EXIM व्यापार प्रवाह में भी सहायता करेंगी। विश्व स्तरीय समुद्री टर्मिनल सुविधाएं, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देती हैं,

सुदूर पूर्व, यूरोप, मध्य-पूर्व, अफ्रीका और अमेरिका के बीच अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन पर चलने वाले मुख्य लाइन मेगा

जहाजों को संभालने में सक्षम अत्याधुनिक टर्मिनल सुविधाओं का निर्माण करने के लिए दक्षता और आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाती हैं।

हरित बंदरगाह पहल

इस परियोजना के मूल में पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता निहित है। वधावन बंदरगाह के विकास की परिकल्पना

एक "हरित क्षेत्र" पहल के रूप में की गई है, जिसमें संधारणीय प्रथाओं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में न्यूनतम

व्यवधान पर जोर दिया गया है। सावधानीपूर्वक योजना और परामर्श के माध्यम से, हम प्रगति और संरक्षण के बीच

सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

वधावन में प्रस्तावित बंदरगाह का उद्देश्य संधारणीय समाधानों को एकीकृत करना है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने से लेकर जहाजों के लिए तटवर्ती बिजली जैसे कुशल बंदरगाह संचालन शामिल हैं और बंदरगाह पारिस्थितिकी तंत्र में केवल विद्युत या हरित ईंधन परिवहन वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। हरित पहल और नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर, वीपीपीएल शून्य उत्सर्जन बंदरगाह बनकर भारत में बंदरगाह विकास के लिए नए मानक स्थापित करने की आकांक्षा रखता है, जिससे एक संधारणीय और समृद्ध भविष्य की शुरुआत होगी।

परियोजना विकास रोजगार के अवसर पैदा करेगा और टर्मिनलों के निर्माण और संचालन के दौरान स्थानीय युवाओं

के कौशल विकास में सहायता करेगा और जिन मछुआरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उन्हें राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। परियोजना आगे की आर्थिक गतिविधि को जोड़ेगी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,00,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा

करने की क्षमता भी रखती है।

वधावन बंदरगाह के असंख्य लाभों के बारे में बात करते हुए, श्री. वाघ ने कहा, "वधावन बंदरगाह की रणनीतिक

स्थिति कंटेनर यातायात को सुविधाजनक बनाएगी। बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय और भारतीय तटों को जोड़ेगा, जिससे पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी आएगी और रसद लागत कम होगी। इसके अलावा, बंदरगाह वापी, इंदौर, कर्नाटक

और महाराष्ट्र में स्थित उद्योगों की EXIM आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। अमतिथ काल 2047 के तहत

300MTPA के साथ एक मेगा पोर्ट विकसित करने का विजन वधावन पोर्ट द्वारा पूरा किया जाएगा

जनेप्रा के बारे में:

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) भारत में प्रमुख कंटेनर-हैंडलिंग बंदरगाहों में से एक है। 26 मई, 1989 को अपनी स्थापना के बाद से, जनेप्रा एक बल्क कार्गो टर्मिनल से देश के प्रमुख कंटेनर बंदरगाह में बदल गया है। इस

प्रकार, जेएनपीए के समृद्ध अनुभव का लाभ उठाते हुए, भारत सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन का जिम्मा जनेप्रा को सौंपा है।

वर्तमान में, जेएनपीए पांच कंटेनर टर्मिनल - एनएसएफटी, एनएसआईसीटी, एनएसआईजीटी, बीएमसीटी और एपीएमटी संचालित करता है। पोर्ट में सामान्य कार्गो के लिए एक उथले पानी का बर्थ भी है। जनेप्रा पोर्ट पर मौजूद

एक लिक्विड कार्गो टर्मिनल का प्रबंधन बीपीसीएल-आईओसीएल कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त,

नवनिर्मित तटीय बर्थ अन्य भारतीय बंदरगाहों को जोड़ता है और तटीय कंटेनरों के आवागमन को बढ़ाने में मदद करता है। 277 हेक्टेयर भूमि पर बसा, जेएनपीए भारत में निर्यात-उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक

बुनियादी ढांचे के साथ एक सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए बहु-उत्पाद एसईजेड का संचालन भी करता है।

मीडिया पूछताछ के लिए, कृपया संपर्क करें:

जनेप्रा:

अंबिका सिंह वरिष्ठ प्रबंधक (मार्केटिंग),

जनेप्रा मोबाइल: +919769769100

ई-मेल: ambikasingh@jnport.gov.in

**PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE**

Cabinet gives approval for

**'Development of an all-Weather Greenfield deep draft Major Port at Vadhvan in
Maharashtra'**

Mumbai, June 20, 2024 – The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for setting up a Major Port at Vadhvan near Dahanu in Maharashtra by Vadhvan Port Project Limited (VPPL) an SPV formed by Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) and Maharashtra Maritime Board (MMB) with a shareholding of 74% and 26% respectively. The Vadhvan Port will be developed as an all-weather Greenfield deep draft Major Port at Vadhvan, Palghar District, Maharashtra on 'Land Lord' model.

Speaking on this momentous occasion, Chairman of Jawaharlal Nehru Port Authority, Unmesh Sharad Wagh commented, "As we set sail towards the development of the Vadhvan port, it brings

us immense pride and eager anticipation to unveil the collaborative effort between the Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) and the Maharashtra Maritime Board. This alliance aims to cater to the burgeoning maritime traffic, marking the dawn of a new chapter filled with growth and opportunities. The project will be implemented by Vadhvan port Project Limited a SPV of JNPA and MMB. We express our sincere gratitude to Hon'ble Union Minister Shri Sarbananda Sonowal, Ministry of Ports Shipping and Waterways, and Hon'ble Secretary Shri T

K Ramachandran, Ministry of Ports Shipping and Waterways for their leadership and guidance for charting the course of the port.”

Vadhvan Port Outlay

The total project cost, including the component of land acquisition, is ₹ 76,220 Cr. This will include core infrastructure, Terminals and other commercial infrastructure in PPP Mode and The Port infrastructure comprises of 9 container terminals, each of 1000 meters length, 4 multipurpose

berths, 4 liquid cargo berths, a Ro-Ro berth, a coastal cargo berth and a Coast Guard berth.

The

project involves reclamation of 1,448 hectares in offshore area and construction of 10.14 kms of breakwater, container/cargo storage areas. The cabinet also approved the establishing road

connectivity between the Port and National Highways by MoRTH and rail linkage to existing rail network and the upcoming Dedicated Rail Freight Corridor by MoR.

India's trade policies and the maritime transport sector developments have resulted in high growth of containerization in the country. India's maritime sector is set to transform with a comprehensive roadmap launched during the Global Maritime India Summit. The Amrit Kaal Vision 2047, formulated by the Ministry of Ports, Shipping & Waterways, builds on the Maritime

India Vision 2030 and aims to develop world-class ports and promote inland water transport, coastal shipping, and a sustainable maritime sector. The capacity in three major container handling ports in the west coast will be fully utilised by 2029 and capacity requirements to the extent of 24 million TEU's and this capacity is expected to be met from Vadhvan port.

The proposed deep draft all-weather Major Port at Vadhvan will augment the national container handling capacity by 23.2 million TEUs and will facilitate calling of mega size container vessels capable of carrying 24,000 TEUs. With the development of Vadhvan port, India will be one among top 10 container ports in the World. The capacities created will also aid EXIM trade flow through IMEC (India Middle East Europe Economic corridor) and INSTC (International North South Transportation Corridor). The world class maritime terminal facilities, promote public private partnerships (PPP), leverage efficiencies and modern technologies to create state of the art

terminal facilities capable of handling mainline mega vessels plying on international shipping lanes between Far East, Europe, Middle-East, Africa and Americas.

Green Port Initiative

At the heart of this project lies a commitment to environmental stewardship. The development of the Vadhvan port is envisaged as a "greenfield" initiative, emphasizing sustainable practices and

minimal disruption to local ecosystems. Through meticulous planning and consultation, we strive to achieve harmony between progress and conservation. The proposed port at Vadhvan aims to integrate sustainable solutions, ranging from renewable energy adoption to efficient port operations like shore power for ships and only electrical or green fuel transport vehicles will be allowed in Port ecosystem. By embracing green initiatives and innovative technologies, VPPL aspire to set new benchmarks for port development in India by being a zero emission Port,

ushering in a sustainable and prosperous future.

The project development will create employment opportunities and aid in skilling of the local youth both during construction and operationalisation of the terminals and fishermen whose livelihood will be adversely affected will be compensated as per State Govt policies. The Project will add to further economic activity and also have potential for direct and indirect employment opportunities for more than 10,00,000 individuals directly and indirectly. Talking about the myriads advantages of the Vadhvan port, Mr. Wagh stated, "The strategic placement of the Vadhvan port will facilitate the call of container traffic. The port will bridge international and Indian coasts that will accelerate the economies of scale and mitigate the logistics cost. Moreover, the port will also address the EXIM needs of industries situated in Vapi, Indore, Karnataka and Maharashtra. The vision under Amrit Kaal 2047 to develop a mega Port with 300MTPA will be fulfilled by Vadhvan Port.

About JNPA:

The Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) is one of the premier container-handling ports in India. Since its inception on May 26, 1989, JNPA has transformed from a bulk cargo terminal into the premier container port in the country. As such, leveraging on rich experience of JNPA, the Govt of India has entrusted the implementation of the project to JNPA.

Currently, JNPA operates five container terminals - NSFT, NSICT, NSIGT, BMCT and APMT. The Port also has a Shallow Water Berth for general cargo. A Liquid Cargo Terminal present at the JNPA Port is managed by the BPCL-IOCL consortium. Additionally, the newly-constructed the coastal berth links other Indian ports and facilitates enhancing the traffic of coastal containers.

Nestled across 277 hectares of land, JNPA also operates a meticulously designed multi-product SEZ, with state-of-the-art infrastructure, to boost export-oriented industries in India.

For media enquiries, please contact:

JNPA:

Ambika Singh

Sr. Manager (Marketing), JNPA

Mob: +919769769100

E-mail: ambikasingh@jnport.gov.in